

सं० 27/10/2013-एस०आर०एस०
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखण्ड ।

18 DEC 2013

विषय:-दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट् याचिका संख्या 72(एस०/बी०)/2012 में श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

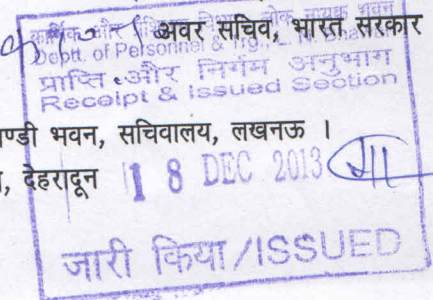
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट् याचिका संख्या 72(एस०/बी०)/2012 में श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के प्रत्यावेदन पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा भारत सरकार को निर्देशित किया गया है कि दाम्पत्य नीति के अनुसार श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता का उत्तराखण्ड राज्य आवंटन पर विचार किया जाए । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री बिष्ट की पत्नी उत्तराखण्ड में नियुक्त हैं तथा श्री बिष्ट दाम्पत्य नीति से आच्छादित हैं । अतः समिति द्वारा उनका राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड किये जाने कि संस्तुति की गयी ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री किशोर सिंह बिष्ट, अवर अभियन्ता का राज्य पुनरावंटन दाम्पत्य नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिये किया जाता है ।

3. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)



प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून